मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्षः 9 अंक 126
बुधवार, 18 नवम्बर 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

किसी उम्मीदवार को अपनी सीट आरक्षित कराने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को SC/ST समुदाय के लिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है। अगर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या इन समुदायों की आबादी के अनुपात में है, तो सरकार के इस फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

याचिकाकताओं ने 'जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961' में सरकार द्वारा 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। इस संशोधन में कहा गया है कि SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेट (बारी-बारी से बदलना) करने की प्रक्रिया अगले आम चुनाव से शुरू मानी जाएगी।

याचिकाकताओं का आरोप है कि इससे पिछले रोटेशन का इतिहास खत्म हो गया है और इसका मतलब यह है कि कुछ निर्वाचन



क्षेत्र, जिन्हें पुराने साइकिल के आधार पर आरक्षित होना चाहिए था, वे अब आरक्षित नहीं होंगे। वकील विपिन सांघी ने कहा, 'नए नियमों को लागू करना अपने आप में पिछले रोटेशन चक्र को नजरअंदाज करने का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता खासकर तब, जब संबंधित चुनावी क्षेत्र काफी हद तक अभी भी मौजूद हैं भले ही उनकी सीमाएं, इलाके या संख्यात्मक नाम बदल गए हों।'

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूछा, 'क्या मतदाताओं या उम्मीदवारों को यह अधिकार है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित करवा सकें?' पीठ ने कहा, 'किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करवाने का अधिकार नहीं है।'

नियमों के अनुसार, SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, चुनाव वाले राज्य या लोकतांत्रिक इकाई में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। किसी का भी यह दावा नहीं है कि SC/ST समुदाय के लिए जरूरी प्रतिशत में सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं।'पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि संशोधित नियम संविधान द्वारा अनिवार्य आरक्षण नीति के अनुरूप हैं। हालांकि, पीठ ने याचिकाकताओं को यह छूट दी कि वे संबंधित प्राधिकरण से अपने अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए कह सकते हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2006 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को किया बरी, निचली अदालत की उम्रकैद की सजा रद्द

कोलकाताा, 17 नवम्बर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2006 के सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले के तीन दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का कोई ठोस सबूत नहीं है। निचली अदालत ने पूर्व बर्धमान जिले के पूर्वस्थली में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले के तीनों आरोपियों को 2018 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर के अपने फैसले में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 के तहत दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच सबूत का एक बुनियादी हिस्सा होती है। उसने कहा कि अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोप को साबित करने में

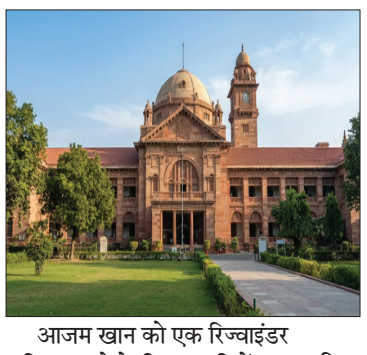


पूरी तरह नाकाम रहा है और मामले की जांच भी विफल रही है। खंडपीठ ने कहा, ₹दुष्कर्म के आरोप दर्ज किए जाने के अलावा पीड़िता के साथ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसने कहा कि यह कानूनी रूप से स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष के लिए आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करना अनिवार्य है। खंडपीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर आरोपियों के दोषी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकताओं के वकील ने पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह नहीं की। उसने कहा कि यह भी एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि आईपीसी की धारा-376 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि हो सकती है, बशर्ते उसकी गवाही त्रुटिहीन हो और अन्य प्रमाणित तथ्यों के साथ मेल खाती हो।

आजम खान की ईडी गिरफ्तारी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 10 दिसंबर को करेगा सुनवाई

इलाहाबाद, 17 नवम्बर। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसंबर तय की। मंगलवार को दोनों पक्षों की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए। अदालत के आदेश के अनुपालन में निदेशालय ने एक हलफनामा दाखिल किया।

आजम खान की ओर से भी एक हलफनामा दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को हलफनामों में दिए गए बयानों का खंडन करने के लिए समय दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को भी एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।



आजम खान को एक रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए 10 दिनों तक का समय दिया। अदालत ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गयी गिरफ्तारी के संबंध में आजम खान की राहत की मांग वाली याचिका पर उचित आदेश पारित करेगी। मंगलवार को आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आगामी चुनावों से पूर्व खान के खिलाफ यह कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और उनकी गिरफ्तारी से पूर्व अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

सिब्बल ने कहा कि दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के भीतर आजम खान को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना राजनीति से प्रेरित कदम है जो 2027 के उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने के लिए उठाया गया है। सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 31 अक्टूबर, 2026 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे।

पहला क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम 2027 की मेजबानी करेगा भारत, मुंबई में होगा आयोजन; पीएम मोदी ने की घोषणा

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने घोषणा की है कि अगले साल पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम का आयोजन मुंबई में होगा। भारत पहली बार क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम 2027 की मेजबानी करेगा। वहीं क्वाड बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिजों को लेकर कई नए समझौते किए जाने की जानकारी दी। इन समझौतों से वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और विदेशी आपूर्तिकताओं पर निर्भरता और दबाव की आशंकाओं को कम करना उद्देश्य है।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना का प्रस्ताव दिया है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, कोस्ट गार्ड सहयोग और नाविकों की सुरक्षा को मजबूत करेगी।

आसियान देश भी इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक हैं। अगर इस बारे में ठोस कदम उठाया जाता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक रवैये के खिलाफ आसियान देशों के साथ सहयोग स्थापित करने में जुटे भारत की कोशिश की यह भारी जीत होगी।

पीएम मोदी ने आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा और आसियान-भारत परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान का भी सुझाव दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच सहयोग और गहरा होगा।

शिखर सम्मेलन को संबोधित



करते हुए मोदी ने कहा कि, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया एक के बाद एक अनेक संकटों से गुजरी है। आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है, शांति, स्थिरता और पूवार्नुमेयता की। इस संदर्भ में इस वर्ष की थीम, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टूगेदर विशेष महत्व रखती है। भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से तय हो। हमारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी। हम मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं। पिछले बारह वर्षों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है। अब हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देनी है।

इस साझेदारी में आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटल है और अटल रहेगी। आज की बैठक हमारी व्यापक सामरिक साझेदारी को नई ऊंचाई प्रदान करेगी और एक सुरक्षित, समावेशी, समृद्ध इंडो-पैसिफिक के निर्माण में योगदान देगी।

मोदी ने आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई तथा कहा कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों पक्षों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच साझा मूल्य, समान वैश्विक दृष्टिकोण और गहरी सांस्कृतिक संबद्धता ने साझेदारी को नया आयाम दिया है।

जम्मू-कश्मीर में काम करने वाली कंपनियां स्थानीय युवाओं को दें रोजगार: उमर अब्दुल्ला

कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में अपना कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर बाहर के लोगों को नौकरी देने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब्दुल्ला ने यह बात जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने के दौरान कही। उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर सरकार सभी क्षेत्रों का समान विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब्दुल्ला ने कहा कि कंपनियों को स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए छह महीने से एक साल तक का समय दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने



कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहां के युवाओं को केवल अपनी क्षमता दिखाने का मौका चाहिए।

कठुआ में लोगों को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, हम यह बहाना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवा उपलब्ध नहीं हैं। हम आपको अपने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए छह महीने या एक साल का समय दे सकते हैं। हमारे यहां अकादमियां, प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं।

शेख हसीना की वापसी से पहले बांग्लादेश में दहशत, ढाका एयरपोर्ट के पास दो धमाकों से मची अफरा-तफरी

ढाका, 17 नवम्बर। बांग्लादेश में संभावित राजनीतिक हिंसा की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाए जाने के बीच ढाका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दो बम विस्फोट हुए जिसमें तीन राहगीर घायल हो गए। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, यह घटना सोमवार रात हुई। अखबार ने पुलिस के हवाले से बताया कि एक बम



हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहरी द्वार के पास फटा, जबकि दूसरा हवाई अड्डे और फ्लाईओवर को जोड़ने वाले मार्गों के पास जसीमुद्दीन इलाके में फटा। ये विस्फोट अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगले महीने प्रस्तावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर बढ़े तनाव के बीच हुए हैं। हसीना अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर देश छोड़कर चली गईं और भारत में रह रही हैं।

हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि इन विस्फोटों का हसीना से कोई संबंध है या नहीं। हवाई अड्डा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी कमरुल इस्लाम तालुकदार के अनुसार, उपद्रवियों ने दोनों बम विस्फोट किये, जिससे तीन राहगीरों को मामूली चोटें आईं। उन्होंने बताया कि बम एक फ्लाईओवर से फेंके गए थे और इसके बाद से सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए गए हैं। हसीना की संभावित वापसी को लेकर पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रेन, बसों और बैंकों को निशाना बनाकर की गई आगजनी भी शामिल है। पुलिस ने इन घटनाओं में से कई के लिए अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद अवामी लीग के राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध



NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW



SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
Std. XI & XII (Sci.)
NEET
JEE (Main & Advance)
MHT-CET
Polytechnic & Engg
Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

TIWARI'S SARASWATI CLASSES
— Since 1992 —
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
34+ Years of Academic Excellence
Experienced & Dedicated Faculty
Personal Attention
Printed Notes & Regular Tests
Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र



-ललित गर्ग

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मयार्दा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13-14 नवंबर 2026 को आयोजित भारत समिट इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों-जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे एंटी-भारत समिट तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है-क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं।

यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और वोट चोर-गद्दी छोड़ जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए?

लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति-भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए-क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को भारत विरोधी या हर आलोचना को विदेशी साजिश बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं।

इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण-सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है-विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे।

यदि किसी राजनीतिक दल को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपना वैकल्पिक मॉडल देना होगा। केवल यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र पर खतरे का दावा प्रमाण मांगता है। चुनावी पराजय का उत्तर विदेशी मंच नहीं, जनविश्वास होता है। इसी तरह सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी आत्ममंथन करना चाहिए। यदि कोई विपक्ष लोकतंत्र या चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसे केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करने के बजाय पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और संवाद के माध्यम से जनता के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास केवल भाषणों से नहीं, संस्थाओं के व्यवहार से बनता है। भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में देश की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाना एक ऐसी परंपरा को जन्म दे सकता है जिसका भविष्य में दुरुपयोग किसी भी दल के विरुद्ध हो सकता है। आज यदि सत्ता पक्ष के विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य बना दिया गया, तो कल यही हथियार किसी दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह प्रश्न कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं, बल्कि भारत बनाम राजनीतिक अवसरवाद का होना चाहिए। भारत समिट सचमुच भारत को विश्व के साथ संवाद का नया मंच बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि भारत के नाम पर आयोजित मंच भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई को विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बना देता है, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत को विदेशी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की राजनीतिक नियति तय करने का अधिकार केवल भारत की जनता को होना चाहिए। सत्ता किसी विदेशी समर्थन से नहीं, लोकतांत्रिक जनादेश से मिलती है और जाती है। अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति यही है कि हम सरकार की कठोर आलोचना कर सकें, विपक्ष के तर्कों को सुन सकें, विदेशी विचारों से संवाद कर सकें, लेकिन निर्णायक अधिकार भारतीय नागरिक के हाथ में रहे। भारत की राजनीति में मतभेद रहें, मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन संप्रभुता से समझौता न हो। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन राष्ट्रहित की सीमा लांघकर नहीं। क्योंकि सरकार बदल सकती है, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, चुनावी परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संप्रभुता किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से बड़ी है। यही भारत की लोकतांत्रिक मयार्दा है और यही उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी।

सपा-कांग्रेस गठबंधनः सीटों के पेच में उलझती सियासी राह



अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चचाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है।

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के 'बड़े भाई' की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवंबर की औपचारिक बैठक को तीन-चार दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है।

गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों

हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
मार्गदर्शन

सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत चार फीसदी से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है।

अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है—'जिताऊ क्षमता')। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है, और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई सहयोगी दल अपनी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से अधिक सीटों की जिद पकड़ लेता है और कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारता है, तो उसका सीधा लाभ विरोधी खेमे को मिलता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का कड़वा अनुभव दोनों दलों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। उस समय सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी गई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसका खामियाजा पूरे गठबंधन को सत्ता से दूर रहकर भुगतना पड़ा था। सपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि 2027 में 2017 की उस ऐतिहासिक भूल को दोहराया जाए। दूसरी ओर, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में केवल 50 या 60 सीटों पर सिमट जाती है, तो इससे न केवल राज्य के शेष हिस्सों में उसका संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उसके मनोबल और सौदेबाजी की ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां पिछली बार सपा के विधायक जीते थे या सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे स्थानीय स्तर पर सपा के नेताओं और कार्यकताओं में असंतोष पनपना स्वाभाविक है।

इस सियासी रस्साकशी के बीच यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान केवल दो ध्रुवों तक सीमित नहीं है। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने मजबूत बूथ प्रबंधन, सामाजिक इंजीनियरिंग और डबल इंजन सरकार की योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोटों का जरा सा भी बिखराव सपा और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह दोहराया है कि 'इंडिया' गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। लेकिन शीर्ष नेताओं की यह सद्भावना तभी फलीभूत हो सकती है जब वह जमीनी कार्यकताओं के स्तर तक पहुंचे। यदि सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही सूची लीक होने और एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास का संदेश जाएगा।

दरअसल अब 17 नवंबर की बैठक का टलना कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है। राजनीति को संभावनाओं और समझौतों की कला कहा जाता है। आने वाले दिनों में जब दोनों दलों की समन्वय समितियां आमने-सामने बैठेंगी, तो उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी और अहं के टकराव से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। कांग्रेस को यह स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की धुरी समाजवादी पार्टी ही है और उसकी सांगठनिक ताकत के बिना भाजपा को चुनौती देना असंभव है। वहीं, समाजवादी पार्टी को भी बड़े भाई का उदार हृदय दिखाते हुए कांग्रेस को इतनी सम्मानजनक हिस्सेदारी अवश्य देनी होगी, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक और अल्पसंख्यक मतदाता पूरे उत्साह के साथ गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सके। सीटों की इस बिसात पर यदि दोनों दल अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर केवल 'जीत' के साझा लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से बात बन सकती है। अन्यथा, तालमेल की यह देरी और आपसी अविश्वास 2027 की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही विपक्ष की धार को कुंद कर सकता है।

सटीक जनसंख्या आँकड़ों के बिना नीतियों की सफलता अधूरी

- डॉक्टर सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र में शासन की सफलता केवल योजनाएँ बनाने और बजट आवंटित करने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि सरकार की नीतियाँ समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को कितना समझती हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी क्या है, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कितने शहरी क्षेत्रों में, कितने परिवार गरीबी, अशिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं—इन सभी प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर जनगणना से मिलता है। इसलिए जनगणना केवल लोगों की गिनती करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का सबसे व्यापक माध्यम है।

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय समाज में विश्वसनीय जनगणना आँकड़ों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। वर्ष 2011 के बाद प्रस्तावित जनगणना 2027 इसलिए ऐतिहासिक महत्त्व रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से देश को लंबे अंतराल के बाद नई जनसांख्यिकीय तस्वीर प्राप्त होगी। डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन डेटा संग्रह और वास्तविक समय में निगरानी जैसी व्यवस्थाएँ इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल तभी सार्थक होगा, जब आँकड़ों की शुद्धता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो।



- डॉ. सत्यवान सौरभ

विश्वसनीय जनगणना का पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। भारत में खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अनेक योजनाएँ जनसंख्या संबंधी आँकड़ों पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवासीय आवश्यकताओं का आकलन, सटीक आँकड़े नीति निर्माण की बुनियाद तैयार करते हैं। यदि जनगणना में किसी क्षेत्र की आबादी कम दर्ज होती है, तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में संसाधन नहीं पहुँच पाते। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीबों, प्रवासी श्रमिकों, बेघर लोगों और वंचित समुदायों को उठाना पड़ता है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष संसाधनों का न्यायसंगत वितरण है। सरकार को यह तय करना होता है कि कहाँ नए विद्यालय खोले जाएँ, किन क्षेत्रों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है, कहाँ सड़क, पेयजल और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा किस क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिले। उदाहरण के लिए, तेजी से बढ़ती शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, आवास और स्वच्छता सुविधाओं की माँग अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि आधारित आधारभूत संरचना और शिक्षा की विशेष आवश्यकता हो सकती है। जनगणना के विश्वसनीय आँकड़े इन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता करते हैं।

जनगणना का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भी गहरा संबंध है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में जनसंख्या संबंधी आँकड़ों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या में होने वाले बदलावों को समझे बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन स्थापित करना कठिन है। इसी प्रकार वित्त आयोग को राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण संबंधी सिफारिशें तैयार करने में जनसांख्यिकीय तथ्यों सहित अनेक मानकों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार जनगणना के आँकड़े केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संतुलन के भी आधार हैं।

हालाँकि, विश्वसनीय जनगणना सुनिश्चित करना आसान कार्य नहीं है। भारत की भौगोलिक विविधता, विशाल जनसंख्या, सामाजिक विषमताएँ और तेजी से बदलती जीवनशैली इसके सामने अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या की सही गणना सुनिश्चित करना है। प्रवासी श्रमिक, बेघर नागरिक, घुमंतू समुदाय, दूरदराज के आदिवासी समूह और अस्थायी रूप से रहने वाले लोग अक्सर गणना की प्रक्रिया से छूट सकते हैं। महानगरों में काम की तलाश में आने वाले श्रमिकों का निवास अस्थायी होता है। ऐसे लोगों की सही गणना और उपयुक्त स्थान पर उनका पंजीकरण एक जटिल प्रशासनिक चुनौती है। यदि ये समूह आँकड़ों से बाहर रह जाते हैं, तो उनकी वास्तविक समस्याएँ भी नीतिगत प्राथमिकताओं में पीछे छूट सकती हैं।

दूसरी चुनौती डिजिटल असमानता है। जनगणना में मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन निगरानी का उपयोग प्रक्रिया को तेज तथा व्यवस्थित बना सकता है, लेकिन देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति, तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता और डिजिटल साक्षरता का अभाव दूरस्थ ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी प्रणाली में गड़बड़ी या डेटा अपलोड करने में त्रुटि भी आँकड़ों की गुणवत्ता प्रभावित कर सकती है।

तीसरी चुनौती मानवीय और प्रशासनिक त्रुटियों से जुड़ी है। जनगणना का बड़ा हिस्सा गणनाकर्मियों द्वारा घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने पर आधारित होता है। यदि गणनाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले या प्रश्नों की व्याख्या में एकरूपता न हो, तो गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। कई बार उत्तरदाता भी सामाजिक संकोच, जानकारी के अभाव अथवा सरकारी लाभ प्रभावित होने की आशंका के कारण सही जानकारी देने से बचते हैं। भाषा, स्थानीय बोलियों और सामाजिक परिस्थितियों की विविधता इस समस्या को और जटिल बनाती है।

इसके साथ ही निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का प्रश्न भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डिजिटल युग में नागरिकों के मन में यह आशंका हो सकती है कि उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। यदि लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि उनकी जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रहेगी, तो वे जनगणना में सहयोग करने से हिचक सकते हैं। इसलिए डेटा सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि जनगणना की विश्वसनीयता से जुड़ा सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रश्न भी है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए सबसे पहले गणनाकर्मियों का व्यापक और व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्हें स्थानीय भाषा, सामाजिक संरचना, प्रश्नावली और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। दूसरा, वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि डेटा संग्रह के दौरान ही असामान्य प्रविष्टियों, दोहराव और संभावित त्रुटियों की पहचान हो सके। तीसरा, स्वतंत्र सत्यापन और नमूना आधारित पुनः जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आँकड़ों की गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल माध्यमों के साथ पारंपरिक गणना विकल्प भी उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि तकनीकी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों की आबादी छूटने न पाए। प्रवासी श्रमिकों, बेघर नागरिकों, घुमंतू समुदायों और दूरस्थ बस्तियों तक पहुँचने के लिए विशेष रणनीति बनाई जानी चाहिए। जनगणना के उद्देश्य, प्रक्रिया और गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के बारे में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है। नागरिकों को यह समझाना होगा कि सही जानकारी देना उनके अपने अधिकारों और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

अंततः जनगणना की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने लोगों की गणना हुई, बल्कि इससे तय होनी चाहिए कि प्राप्त आँकड़े देश की वास्तविक सामाजिक तस्वीर को कितनी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। विश्वसनीय आँकड़े सरकार को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, जबकि गलत आँकड़े अच्छी नीतियों को भी गलत दिशा में ले जा सकते हैं। भारत की जनगणना 2027 को केवल एक प्रशासनिक अभ्यास के बजाय लोकतांत्रिक जवाबदेही, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। आखिरकार, जिस देश की सरकार अपने नागरिकों की वास्तविक संख्या, आवश्यकताओं और परिस्थितियों को सही ढंग से समझती है, वही देश विकास की यात्रा में किसी को पीछे छोड़ने से बच सकता है। सही जनगणना ही सही नीति, न्यायपूर्ण वितरण और मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त है।

अखिलेश की दुखती नब्ज ने बढ़ाया कांग्रेस का हौसला

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक पर विराम लग गया है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों दलों के बीच शुरूआती मांगों में बड़ा अंतर होने के कारण अंतिम सहमति बनने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसकी वजह से दोनों के बीच कई बार बैठक टलने या गर्मागर्मी देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की कि कांग्रेस ने गठबंधन में 181 सीटों की मांग रखी है। वहीं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयानों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 175 से 200 सीटों का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर, अन्य मीडिया स्रोतों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी जीतने की क्षमता के आधार पर कांग्रेस को केवल 60 से 70 या अधिकतम 75 से 80 सीटें ही देने पर विचार कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव की तारीखें करीब आने तक यह खींचतान



-संजय सक्सेना

जारी रह सकती है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर पार्टियां शुरूआती दौर में अधिक सीटों की मांग रखती हैं, ताकि मोलभाव के बाद एक सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंचा जा सके। इसलिए, अंतिम समझौते की घोषणा होने में अभी कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है, क्योंकि दोनों दल अपने-अपने कैडर और स्थानीय नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि दोनों के बीच समझौता टूटने की संभावना भी है या नहीं और सीटों का गणित क्या कहता है, यह जान लेना भी जरूरी है। इस बात पर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग राय है कि क्या कांग्रेस को झुकना पड़ेगा या गठबंधन टूट भी सकता है। कई राजनीतिक जानकारों के विश्लेषणों के अनुसार, दोनों ही पार्टियां इस बात से वाकिफ हैं कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा होने से उन

गोदाम में सेंध लगाकर 14 .44 लाख रुपये का तांबा चुराने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार



भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी के गोदाम क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले पांच आरोपियों को नारपोली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का तांबे का सामान और वारदात में इस्तेमाल किया गया टेम्पो बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, नारपोली पुलिस थाना क्षेत्र के राहनाल ग्राम पंचायत अंतर्गत सद्गुरु कंपाउंड स्थित एक गोदाम में 5 से 12 नवंबर के बीच चोरों ने शटर तोड़कर प्रवेश किया और वहां रखा 14 लाख 44 हजार रुपये कीमत का तांबे का विभिन्न सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कादबाने और पुलिस निरीक्षक अतुल अड़ूरकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र पाटील, पुलिस उपनिरीक्षक आकाश पवार तथा अपराध प्रकटीकरण शाखा की टीम ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त मुखबिरों की मदद से जांच शुरू की। पुलिस टीम ने महज दो दिनों में संदिग्धों का पता लगाकर पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शौकत उर्फ वसीम अकबरअली खान (28), गयासुद्दीन सलाहुद्दीन चौधरी (21), सलमान शाबान अली खान (33), अंबिया सजाउद्दीन मिर्जा (32), सभी निवासी कौसा, मुंब्रा तथा अब्दुल हासिम वदुत खान (38), निवासी उल्हासनगर नंबर-5 के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपियों ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किया गया टेम्पो और 14 लाख 37 हजार रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद किया है। इस मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक आकाश पवार कर रहे हैं।

बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर मीरा-भायंदर में भावभीनी श्रद्धांजलि, कलादालन देखने उमड़े नागरिक



मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। हिंदूहृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मीरा-भायंदर शिवसेना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिले के पालक मंत्री प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में न्यू गोल्डन नेस्ट, भायंदर पूर्व स्थित 'हिंदूहृदयसम्राट पूज्य बालासाहेब ठाकरे कलादालन' में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिवसैनिक और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत बालासाहेब ठाकरे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बालासाहेब के व्यक्तित्व, संघर्ष और उनके विचारों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने मराठी समाज को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी। उनके विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के प्रयास करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बालासाहेब की जीवनगाथा से रूबरू हुई नई पीढ़ी इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बालासाहेब ठाकरे कलादालन रहा। नई पीढ़ी को उनके जीवन, विचारों, कार्टून कला, ऐतिहासिक भाषणों और सामाजिक योगदान से परिचित कराने के उद्देश्य से कलादालन को विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरे दिन निःशुल्क खुला रखा गया था। सुबह से ही स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी संख्या कलादालन देखने पहुंची। यहां प्रदर्शित बालासाहेब के जीवन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरों, उनके द्वारा बनाए गए काटूर्नों, ऐतिहासिक प्रसंगों और उनके कार्यों की जानकारी ने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। नागरिकों ने कलादालन का अवलोकन कर बालासाहेब के जीवन और विचारों को करीब से समझा। कलादालन की नागरिकों ने की सराहना कलादालन देखने पहुंचे नागरिकों ने मीरा-भायंदर में बालासाहेब ठाकरे के जीवन और विचारों को समर्पित इस भव्य एवं ज्ञानवर्धक कलादालन की स्थापना के लिए मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रयासों की सराहना की। नागरिकों का कहना था कि इस तरह के उपक्रमों से नई पीढ़ी को महापुरुषों के विचारों, संघर्ष और सामाजिक योगदान को समझने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर मीरा-भायंदर शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, महिला आघाड़ी, युवा सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित रहे। पूरे परिसर में बालासाहेब ठाकरे के सम्मान में जयघोष गूंजता रहा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से शिवसैनिकों ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों और उनकी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

मीशो और यूट्यूब शॉपिंग ने की साझेदारी , देशभर के कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेंगे कमाई के नए अवसर

मुंबई/पटना। मीशो ने यूट्यूब शॉपिंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देशभर के कंटेंट क्रिएटर्स को कमाई के नए अवसर देना है। इस साझेदारी के तहत योग्य यूट्यूब क्रिएटर्स अपने वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में सीधे मीशो के प्रोडक्ट्स को टैग कर सकेंगे। यूट्यूब के तय शत को पूरा करने वाले ऐसे क्रिएटर्स भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकेंगे, जिनके कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स हैं । क्रिएटर्स के वीडियो के जरिए खरीदारी होने पर उन्हें कमीशन मलेगा। इससे वे अपने दर्शकों को प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। लाखों प्रोडक्ट्स को प्रोमोट कर सकेंगे कंटेंट क्रिएटर्स। इस साझेदारी के जरए कंटेंट क्रिएटर्स को मीशो पर 40 केटेगरी में उपलब्ध 3 करोड़ से अधक प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करने का मौका मलेगा। ये प्रोडक्ट्स 2 लाख से ज्यादा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं । फैशन, ब्यूटी , घर के सजावट और रसोई के सामान जैसे कई प्रोडक्ट्स को क्रिएटर्स अपने रिव्यु वीडियो, स्टाइलिंग वीडियो, शॉपिंग वीडियो और लाइव स्ट्रीम में दिखा सकेंगे।

नवघर मैदान में दीपोत्सव का भव्य समापन, इंदुरिकर महाराज के महाकीर्तन में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

◆मंत्री प्रताप सरनाईक की संकल्पना से पहली बार आयोजित तीन दिवसीय दीपोत्सव बना आकर्षण का केंद्र, हजारों श्रद्धालुओं ने दो घंटे तक खड़े रहकर सुना जीवन मूल्यों का संदेश

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर शहर में हिंदू धर्म, वारकरी संप्रदाय की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिले के पालकमंत्री प्रताप सरनाईक की संकल्पना के तहत शिवसेना द्वारा आयोजित भव्य तीन दिवसीय दीपोत्सव का 16 नवंबर को ऐतिहासिक एवं भक्तिमय वातावरण में समापन हुआ। पूर्वी भायंदर के नवघर मैदान में 14, 15 और 16 नवंबर को आयोजित इस दीपोत्सव के अंतिम दिन प्रसिद्ध कीर्तनकार एच.बी.पी. निवृत्ति महाराज देशमुख उर्फ इंदुरिकर महाराज के महाकीर्तन ने पूरे शहर को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। इंदुरिकर महाराज के कीर्तन को सुनने के लिए नवघर मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिक उमड़ पड़े। मैदान में उमड़ी भारी भीड़ ने आयोजन को विशेष बना दिया। लगभग दो घंटे तक बड़ी संख्या में श्रोता खड़े रहकर महाराज का कीर्तन सुनते रहे। उनके प्रभावशाली अंदाज, हास्यपूर्ण उदाहरणों और सरल भाषा में दिए गए सामाजिक संदेशों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंदुरिकर महाराज ने कीर्तन के माध्यम से दिया सामाजिक जागरूकता का संदेश



अपने खास हास्यपूर्ण और प्रभावशाली अंदाज में इंदुरिकर महाराज ने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने माता-पिता का सम्मान करने, परिवार की अहमियत समझने, शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संदेश दिया। उन्होंने वर्तमान सूखे की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए किसानों और बलिराजा की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों को निराशा से बाहर निकलने और आत्महत्या जैसा कदम न उठाने की अपील की। महाराज ने कहा कि समाज में सकारात्मक विचारों और जागरूकता का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचनाओं के बावजूद वे अपने कीर्तन के माध्यम से समाज प्रबोधन का कार्य निरंतर करते रहेंगे। वारकरी भवन और बालासाहेब ठाकरे के विचारों का किया उल्लेख कीर्तन के दौरान इंदुरिकर महाराज ने मीरा-भायंदर में निर्मित महाराष्ट्र के पहले वारकरी भवन का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रयासों से पिछले वर्ष इस वारकरी भवन का निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। उन्होंने वारकरी संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा वारकरी समाज के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना के संस्थापक हिंदूहृदयसम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के विचारों को याद करते हुए कहा कि बालासाहेब की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ किसी लालच या वाहनों की व्यवस्था से नहीं आती थी, बल्कि उनके विचारों, हिंदुत्व और नेतृत्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था के कारण स्वयं उमड़ती थी। '18 वर्षों के विधायक कार्यकाल में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देखी' : प्रताप सरनाईक दीपोत्सव के इस ऐतिहासिक समापन अवसर पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 18 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नवघर-गोडदेव क्षेत्र की जनता ने हमेशा उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन दिया है, लेकिन इंदुरिकर महाराज के कीर्तन और दीपोत्सव के लिए इतनी विशाल संख्या में लोगों का एकत्रित होना उनके लिए भी एक विशेष अनुभव है। उन्होंने कहा कि लगभग दो घंटे तक हजारों नागरिकों का खड़े रहकर कीर्तन सुनना इस आयोजन की वास्तविक सफलता है।

किआ इंडिया की प्रीमियम एसयूवी सोरेंटो को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

मुंबई। किआ इंडिया ने आज घोषणा की है कि सितंबर 2026 में बुकिंग शुरू होने के बाद से उसकी प्रीमियम एसयूवी किआ सोरेंटो ने 4,500 होलसेल यूनिट्स का आँकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि सोरेंटो की आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिफाइड परफॉर्मेंस, शानदार आराम और व्यापक सुरक्षा के प्रति ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दशार्ती है। इसके आकर्षण को बढ़ाते हुए, कंपनी के 'अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' के तहत तीन साल बाद 70% तक की सुनिश्चित रीसेल वैल्यू भी दी जा रही है।

इस सफलता पर किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, श्री अतुल सूद ने कहा, 4,500 होलसेल यूनिट्स का पड़ाव पार करना किआ सोरेंटो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो ब्रांड के प्रति ग्राहकों के विश्वास को दशार्ता है। हमारा लक्ष्य वैश्विक मानकों की तकनीक और प्रीमियम आराम के साथ ग्राहकों को अपनी श्रेणी से कहीं बेहतर अनुभव देना है। हम अपने ग्राहकों, डीलर पार्टनर्स और सभी हितधारकों के आभारी हैं।

किआ सोरेंटो वैश्विक स्तर पर किआ की पहली कार है, जिसमें रियल-टाइम जनरेटिव एआई पर आधारित किआ एआई असिस्टेंट दिया गया है। 'हे किआ' वॉयस कमांड से सक्रिय होने वाला यह फीचर फॉलो-अप सवालों के जवाब देने के साथ एसी और खिड़कियों को भी नियंत्रित करता है। इसके साथ ही किआ कनेक्ट 2.0 में 85 से अधिक कनेक्टेड-कार फीचर्स, 30 कंट्रोलर्स के लिए ओटीए अपडेट्स और डिजिटल की 2.0 की सुविधा मिलती है।

सोरेंटो दो पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है।

काशीमीरा में बिहार प्रदेश नागरिक मंडल का 31वां सार्वजनिक सूर्यषष्ठी छठ महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न

◆31 वर्षों से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आयोजन कर रहा है बिहार प्रदेश नागरिक मंडल, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्यदेव को अर्घ्य

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर शहर के काशीमीरा, प्रभाग क्रमांक 14 में बिहार प्रदेश नागरिक मंडल द्वारा सार्वजनिक सूर्यषष्ठी व्रत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। 15 नवंबर 2026 को आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में छठ व्रतधारी महिलाओं, पुरुषों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की। उल्लेखनीय है कि



बिहार प्रदेश नागरिक मंडल पिछले 31 वर्षों से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सार्वजनिक आयोजन निरंतर करता आ रहा है। इस आयोजन के माध्यम से मंडल धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे रहा है। छठ महापर्व के अवसर पर व्रतधारियों ने परंपरागत विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया गया। वहीं, अगले दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया गया। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर बिहार प्रदेश नागरिक मंडल के अध्यक्ष मुकेश सिंह, संस्थापक अलख चौबे, संस्थापक सुरेश तिवारी, मुख्य सलाहकार एवं नगरसेवक अनिल भोसले, अचल तिवारी तथा नितेश सिंह सहित मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। छठ पूजा से जुड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी अपनी सहभागिता निभाई। आयोजन के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। बिहार प्रदेश नागरिक मंडल का यह 31 वर्षों से चला आ रहा आयोजन क्षेत्र में बिहार की लोक संस्कृति, धार्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है।

चेंबूर के वासीनाका स्थित अयोध्या नगर झोपड़पट्टी में बढ़ती हुई गंदगी से बीमारी फैलने की आशंका

मुंबई (उत्तरशक्ति)। केंद्र तथा राज्य सरकार जहां पूरे देश में लंबे समय से स्वच्छता अभियान चला रही है वहीं दूसरी तरफ मनपा एम पूर्व विभाग के अंतर्गत आने वाली चेंबूर की अयोध्या नगर झोपड़पट्टी के भरतकुंज सोसाइटी के आस पास गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ है। बढ़ती हुई गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जिसके कारण बीमारी फैलने की संभावना बढ़ गई है । वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहकार आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष दीपक दादा शिंदे ने स्थानीय नगरसेविका और मनपा एम पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त से जल्द से जल्द इस परिसर की साफ सफाई किए



जाने की मांग की है।

मिली जानकारी के अनुसार वासीनाका के अयोध्या नगर स्थित भरतकुंज सोसाइटी और म्हाडा बिल्डिंग नंबर 16 के पीछे के इलाके में कचरे का अंबार लगा हुआ है। जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप फैल रहा है। जिससे मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। खास बात यह है कि लंबे समय से जमा हुए कचरे के ढेर की सफाई के लिए अभी तक न तो कोई मनपा का सफाई कर्मचारी आया और न ही दत्तक बस्ती योजना चलाने वाले आए। जिसके कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहकार आघाड़ी महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष दीपक दादा शिंदे ने स्थानीय नगरसेविका और मनपा एम पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त से कचरे के ढेर की साफ सफाई किए जाने की मांग की है। जिससे बीमारी का प्रकोप न फैल सके।

चेन स्नैचिंग करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

◆200 से 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर अपराध शाखा कक्ष-3 ने सुलझाई वारदात, 1.40 लाख का माल बरामद

वसई-विरार (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा कक्ष-3, विरार की टीम ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई सोने की चेन, वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सहित कुल 1 लाख 40 हजार 532 रुपये का माल बरामद किया है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 5 नवंबर 2026 की रात करीब 10:50 बजे एक महिला अपने पति के साथ स्कूटर से नालासोपारा पूर्व स्थित सनसिटी रोड से वसई की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आए एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के गले से सोने की चेन जबरन खींच ली और मौके से फरार हो गया। इस मामले में महिला की शिकायत पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 601/2026 के



तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अपराध शाखा कक्ष-3 की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर समानांतर जांच शुरू की। रात के समय हुई वारदात और प्रत्यक्ष सबूतों के अभाव के बावजूद पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए पालघर जिले के तलासरी क्षेत्र में लगे लगभग 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित नथू शनिवार (उम्र 30 वर्ष), निवासी तलासरी, जिला पालघर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और महिला से छीनी गई सोने की चेन सहित कुल 1,40,532 रुपये मूल्य का माल बरामद किया है।

आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए नालासोपारा पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने पर उसके खिलाफ इसी प्रकार के कुल चार मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इस कार्रवाई को पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पुलिस आयुक्त संजय शिंदे, पुलिस उपायुक्त संदीप डोईफोडे तथा सहायक पुलिस आयुक्त नितिन पाटील के मार्गदर्शन में अपराध शाखा कक्ष-3 की टीम ने अंजाम दिया।

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी तक पहुंचने में अपराध शाखा की टीम को मिली यह सफलता पुलिस की प्रभावी जांच का उदाहरण है।

भिवंडी न्यायालय के 130 कर्मचारी सुधारित वेतनश्रेणी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनश्रेणी लागू करने की मांग को लेकर शुरू किए गए राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन में भिवंडी न्यायालय के 130 कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। मंगलवार से भिवंडी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तथा दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर न्यायालय के बाहर मौन धरना शुरू कर दिया। भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालय के अधीक्षक जयवंत शिंगोळे तथा दीवानी न्यायालय की सहायक अधीक्षक ज्योति भरत नांगरे के नेतृत्व में 130 कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए।इस अवसर पर अधीक्षक जयवंत शिंगोळे ने बताया



कि संशोधित वेतनश्रेणी की मांग को लेकर इससे पहले कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर संवैधानिक तरीके से शासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था।

इसके बावजूद सरकार की ओर से मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उच्च न्यायालय ने भी 31 जनवरी 2025 को इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। इस आंदोलन के चलते मंगलवार को भिवंडी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तथा दीवानी न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध 1675 मुकदमों का कामकाज प्रभावित हुआ। अचानक कामकाज ठप होने से न्यायालय पहुंचे वादी और प्रतिवादियों को निराश होकर लौटना पड़ा।

केसीएन क्लब निर्झरिणी का दीपावली स्नेह मिलन एवं छठ पूजा विशेष काव्य गोष्ठी संपन्न

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। बोईसर शहर स्थित केसीएन हाउस में राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी के तत्वावधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं छठ पूजा विशेष 157वीं काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, अन्नकूट, भाईदूज एवं छठ पूजा के उल्लास और सांस्कृतिक महत्व को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का सुंदर संगम देखने को मिला।

कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्झरिणी के संरक्षक एवं वरिष्ठ कवि के.के. श्रीवास्तव ने की, जबकि मंच का कुशल संचालन नवरत्न मिश्र अर्पित ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में युवा समाजसेवी एवं उद्यमी यशपाल सिंह उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ कवि एवं बीएआरसी कर्मचारी प्रभुनाथ चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। काव्य गोष्ठी में निर्झरिणी

के अध्यक्ष एवं कवि कुमार कलहंस, कवि शेखर तिवारी, बसंत चौहान, के.के. श्रीवास्तव, प्रभुनाथ चतुर्वेदी तथा नवरत्न मिश्र सहित अन्य रचनाकारों ने अपनी उत्कृष्ट काव्य प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों ने दीपावली की खुशियों, छठ महापर्व की आस्था, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रप्रेम पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि यशपाल सिंह को अंगवस्त्र, सम्मान पत्र, स्मृति चिह्न एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। केसीएन क्लब को अधिक सशक्त, सक्रिय एवं प्रभावशाली बनाने, सामाजिक एकजुटता बढ़ाने तथा संगठन के विस्तार को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। साथ ही आगामी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और समाजहित से जुड़े रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि समाज के अधिकारी एवं कर्मचारी संगठित होकर सामाजिक उत्थान, शिक्षा, जनजागरूकता और आपसी सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दें। सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा सामूहिक प्रयासों से समाज को नई दिशा और मजबूती प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में अल्पाहार के साथ समारोह का समापन हुआ।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com



स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 37 वर्षीय राकेश कुमार गौतम की पीट-पीटकर हत्या

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव में मंगलवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि दूसरे गांव से आए करीब 20 से 25 लोगों ने घर के दरवाजे पर 37 वर्षीय राकेश कुमार गौतम को घेरकर उन पर हमला कर दिया। हमलावरों की पिटाई से राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

बताया जाता है कि राकेश कुमार गौतम का जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।

मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे इसी विवाद को लेकर दूसरे गांव

दूसरे गांव से पहुंचे 20-25 लोगों पर हमले का आरोप, घर के दरवाजे पर हुई वारदात से गांव में तनाव

से बड़ी संख्या में लोग मैनुद्दीनपुर पहुंचे। आरोप है कि घर के सामने दरवाजे पर ही राकेश को घेर लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। गंभीर चोटों के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर पुलिस बल भी गांव पहुंच गया। वारदात के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया जा रहा है। हालांकि, हमले में शामिल लोगों की भूमिका और घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

होटल के कमरे में मिला युवक-युवती का शव

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। कमिश्नरेट के बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर के पास स्थित केजे होटल के एक कमरे में सोमवार की देर रात युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती बड़ागांव निवासी प्रिया केसरी (23) थी। युवक मंडुवाडीह निवासी विकास केसरी (20) था। दोनों रिश्तेदार थे। युवती का शव कमरे में मिला था। उसकी गर्दन कटी हुई थी। जबकि युवक का शव फंदे से लटकता मिला। फॉरेंसिक टीम की जांच में सामने आया कि युवक ने पहले चाकू से युवती का गला रेता और इसके बाद खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। दोनों दोपहर करीब एक बजे होटल पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार, युवक ने युवती का गला बाथरूम में रेता ताकि खून बाथरूम में ही बह जाए। युवती की शादी कहीं और तय होने से युवक नाराज था। आशंका है कि उसने आखिरी बार मुलाकात के बहाने युवती को होटल बुलाया और उसकी हत्या कर दी। बड़ागांव थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि विकास के भाई की साली प्रिया से उसका पहले से प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को भी थी। विकास परचून की दुकान चलाता था, जबकि प्रिया ब्यूटीशियन थी। घटना की सूचना पर डीसीपी गोमती जोन नीतू कादयान भी मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने होटल के कमरे और आसपास के स्थानों का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य और नमूने जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी गोमती जोन ने बताया कि दोनों मृतक आपस में रिश्तेदार थे। युवक ने पहले युवती की हत्या की फिर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने तहरीर दी थी। बताया था कि प्रिया सुबह ही घर से निकली थी। विकास भी लापता था। दोनों के मोबाइल की लोकेशन निकाली। जिसके बाद दोनों का पता चला। कमरा अंदर से बंद था। प्रिया के परिजन थाने पहुंचे।

तंत्र-मंत्र का भय दिखाकर एक लाख रुपये और कीमती सामान ठगने का आरोप

◆ शाहगंज पुलिस ने कथित तांत्रिक को किया गिरफ्तार

शाहगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तंत्र-मंत्र और सोखागिरी का डर दिखाकर ठगी व जबरन वसूली करने के आरोप में शाहगंज पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सफर हुसैन (37) पुत्र अंसार हुसैन निवासी बड़ागांव, थाना शाहगंज के रूप में हुई है।

मामले में आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थाना क्षेत्र के शम्सपुर गांव निवासी नाजरीन बानो ने 16 नवंबर को शाहगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि सफर हुसैन ने खुद को तांत्रिक और सोखा बताकर बड़ागांव स्थित रौजा के पास उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे की बीमारी और घर में तंत्र-मंत्र किए जाने का भय दिखाकर कथित तौर पर एक लाख रुपये नकद और कीमती सामान ले लिया।



पीड़िता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा और गाली-गलौज करता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार 17 नवंबर को दोपहर करीब 1:05 बजे मुखबिर की सूचना पर बड़ागांव रौजा के पास मजार वाले रास्ते से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से कथित तौर पर ठगी की रकम में से 20 हजार रुपये बरामद हुए। इसके बाद मुकदमे में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी की गई।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में रखने की बात कही। पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल सिजाउद्दीन शेख और कांस्टेबल प्रभात कुमार शामिल रहे।

उमेश मिश्र बने जौनपुर के नए जिलाधिकारी, सैमुअल पॉल एन. का हुआ तबादला

प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, छह जिलों को मिले नए डीएम

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। शासन की ओर से जारी तबादला सूची में जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. का भी नाम शामिल है। उनके स्थान पर उमेश मिश्र को जौनपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उमेश मिश्र वर्तमान में नगर विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे।

शासन के इस फैसले के बाद अब जौनपुर जिले की प्रशासनिक कमान उमेश मिश्र संभालेंगे। वहीं, जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में केवल जौनपुर ही नहीं, बल्कि भदोही, चंदौली, गोंडा, श्रावस्ती और शामली समेत छह



जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है। तबादला सूची के अनुसार अनिल कुमार सिंह को भदोही, शैलेश कुमार को चंदौली, रमेश रंजन को गोंडा, उमेश मिश्र को जौनपुर, मनोज कुमार राय को श्रावस्ती तथा प्रवीण वर्मा को शामली का जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा कानपुर और वाराणसी मंडल के मंडलायुक्तों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। विजयेंद्र पांडियन को कानपुर मंडल से हटाकर वाराणसी मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है, जबकि एस. राजलिंगम को वाराणसी से स्थानांतरित कर कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासनिक फेरबदल के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

जौनपुर में नए जिलाधिकारी की नियुक्ति को जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जिले के लोगों की निगाहें नए जिलाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने और उनके आगामी प्रशासनिक निर्णयों पर टिकी हैं।

पीएम राहत और राहवीर योजना से बचाई जा सकती है घायलों की जान: प्रो. प्रमोद

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान के मूट कोर्ट में मंगलवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कुलपति प्रो. आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद यादव ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना एवं राहवीर योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आपातकालीन सहायता, एम्बुलेंस ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार



अथवा नजदीकी अस्पताल की जानकारी के लिए 112 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने राहवीर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को जागरूकता एवं जिम्मेदार व्यवहार से काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में नोडल अधिकारी डॉ. अनुराग मिश्र ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और यातायात नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इसमें दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा एवं लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने तथा नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाने का संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम के अंत में विधि संस्थान के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष प्रो. विनोद कुमार ने अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. वनिता सिंह, डॉ. राहुल राय, डॉ. अंकित कुमार, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. रजित राम सोनकर, डॉ. शुभम सिंह एवं डॉ. आश्रेय दुबे सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

गोपाष्टमी पर मणि मंदिर में पूजी गई गायें

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में धर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली श्रीमणि मंदिर, श्रीधर्मसंघ शिक्षा मण्डल,



दुगार्कुण्ड में मंगलवार को विधि विधान से गोपाष्टमी मनाई गई। मंदिर प्रांगण में स्थित स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में प्रातः 9 बजे से धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में सैकड़ो की संख्या में आये गौभक्तों ने सविधि पूजन अर्चन किया। आचार्य रामानंद पाण्डेय के आचार्यत्व में वैदिक आचार्यों एवं शताधिक बटुकों द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रोच्चार के बीच षोडषोपचार (राजषोपचार) विधि से गऊ पूजन किया गया। सर्वप्रथम गौरी - गणेश पूजन तथा आदित्य सूर्य पूजन किया गया, उसके उपरांत भगवान विष्णु का पूजन कर विधिवत गौपूजन किया गया।

गोपाष्टमी के अवसर पर पर गौशाले में सैकड़ो की संख्या में निवासित शुद्ध देशी गाय, गिर, साहीवाल, गंगातीरी गायों को प्रातःकाल पंचगव्य और पंचामृत स्नान कराया गया, उसके बाद गायों का रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र, मुकुट, स्वर्ण-रजत आभूषण आदि से श्रृंगार किया गया। पूजन के उपरांत सभी गायों को गुड़ और फल के साथ हरे चारे के रूप में साग, मूली, खीरा, लौकी, सेम, गाजर आदि भोग खिलाया गया। अंत मे आरती कर उनकी प्रदक्षिणा की गयी। पूजन में दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में आये भक्तों ने भी सविधि पूजन किया।

धर्मसंघ के महामंत्री पं. जगजीतन पाण्डेय ने गौभक्तों को गऊ सेवा का महात्म्य बताते हुए कहा कि कलिकाल में गौ माता की सेवा ही समस्त पापों का शमन करती है और सर्व सुख प्रदान करती है। सनातन धर्म मे गऊ का विशेष स्थान है, जो स्थान गंगा और गायत्री का है वहीं स्थान गौ का है। धर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का सम्पूर्ण जीवन गौ संवर्धन के लिए समर्पित रहा, गौहत्या बन्दी के लिए उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन सम्पूर्ण देशभर में फैला।

राजमंगल पाण्डेय ने मुख्य यजमान के रूप में पूजन सम्पन्न कराया। गौपूजन में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पं. श्रीकान्त मिश्रा, प्रो. एसपी पाण्डेय, प्रो.शरद धर शर्मा, प्रो. पी एस ब्यादगी, प्रताप बहादुर सिंह, विकास शर्मा, सोनू द्विवेदी, राकेश पाण्डेय, अनुराग शर्मा, प्रिंस द्विवेदी, सुषमा शुक्ला, विकास शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे।

यमराज बन कलाकारों ने दिया यातायात नियमों के पालन का संदेश, सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील, लापरवाही को बताया जानलेवा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जेसीज चौराहे पर अनोखा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कलाकारों ने यमराज का रूप धारण कर वाहन चालकों और राहगीरों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया।



यमराज के वेश में कलाकारों को देखकर चौराहे से गुजर रहे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। कलाकारों ने अनूठे अंदाज में लोगों को समझाया कि सड़क पर की गई छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की। कलाकारों ने संदेश दिया कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। अभियान के माध्यम से लोगों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा को अपनी आदत में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया।

6 दिसंबर की महारैली के लिए बसपा ने भरी हुंकार

बदलापुर से 10 हजार कार्यकर्ता लखनऊ जाने की तैयारी में

बदलापुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मिशन 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार,



17 नवंबर 2026 को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दिशा-निर्देश पर बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वाराणसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी शोभनाथ चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2026 को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में बसपा की विशाल महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से जुटना होगा। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10 हजार लोगों को अपने निजी साधनों से लखनऊ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि यह महारैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटने की अपील की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सुनील कुमार गौतम सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान मिशन 2027 में वर्ष 2007 की सफलता दोहराने और प्रदेश में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनाने का संकल्प भी दोहराया गया।

सोनभद्र में 18 नवंबर को लगेगा वृहद रोजगार मेला, 50 कंपनियां करेंगी युवाओं की भर्ती

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से 18 नवंबर 2026 को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला राबर्ट्सगंज के उरमौरा स्थित डायट मैदान में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। मेले में हिण्डाल्को, टाटा मोटर्स, फिएट इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, फ्लिपकार्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज समेत लगभग 50 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। जिला सेवायोजन कार्यालय के अनुसार रोजगार मेले में प्रतिभाग पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इच्छुक युवा आवश्यक शैक्षिक अभिलेखों के साथ निर्धारित समय पर पहुंचकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

कर्नाटक में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे पीयू के स्वयंसेवक

कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 21 से 27 नवंबर तक आयोजित होगा शिविर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के 10 स्वयंसेवक एवं एक कार्यक्रम अधिकारी मंगलवार को कर्नाटक के लिए रवाना हुए। ये स्वयंसेवक 21 से 27 नवंबर, 2026 तक एसडीएम आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, हासन, कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुलपति प्रो. आर. के. सिंह ने स्वयंसेवकों से संवाद करने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने स्वयंसेवकों से शिविर में प्रदेश की संस्कृति एवं परंपराओं को प्रस्तुत करने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। स्वयंसेवकों ने बताया कि वे लोकगीत, लोकनृत्य, सांस्कृतिक परंपराओं और विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे।स्वयंसेवकों ने बताया कि



शिविर में देश के अन्य नौ राज्यों से आए प्रतिभागियों के साथ संवाद करने और उनकी संस्कृति, कला एवं परंपराओं को जानने-समझने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कुलपति को आश्वस्त किया कि शिविर से लौटने के बाद वे अपने अनुभव और सीख विश्वविद्यालय परिवार के साथ साझा करेंगे।

कुलपति प्रो. सिंह ने सभी स्वयंसेवकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरे उत्साह, अनुशासन और समर्पण के साथ शिविर में प्रतिभाग करें तथा अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें।

इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुषमा मिश्रा (मड़ियाहूं पीजी कॉलेज, मड़ियाहूं) एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

वाराणसी कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 201 दरोगाओं का तबादला; चारों जोन में नई तैनाती

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा ने 201 उपनिरीक्षकों (दरोगाओं) के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। यह आदेश 16 नवंबर 2026 को पुलिस कमिश्नरेट स्थापना बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरित किए गए उपनिरीक्षकों को काशी, वरुणा और गोमती जोन के साथ रिजर्व पुलिस लाइन में तैनाती दी गई है। तबादला सूची के मुताबिक, काशी जोन में 69, वरुणा जोन में 80, गोमती जोन में 14 तथा रिजर्व पुलिस लाइन में 38 उपनिरीक्षकों को भेजा गया है। इस तरह कुल 201 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।

वरुणा जोन में सबसे अधिक 80 उपनिरीक्षकों की तैनाती हुई है, जबकि काशी जोन में 69 दरोगाओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पुलिस लाइन में 38 और गोमती जोन में 14 उपनिरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। इस फेरबदल में महिला उपनिरीक्षकों को भी विभिन्न जोन में तैनाती दी गई है।

पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरण आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन आख्या अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यापक फेरबदल को कमिश्नरेट की पुलिस व्यवस्था में प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

पीबीएल शिक्षण पद्धति से शिक्षा में आएगा बदलाव, विद्यार्थियों में विकसित होगी रचनात्मक सोच: उप शिक्षा निदेशक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), जौनपुर में मंगलवार को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए उप शिक्षा निदेशक एवं डायट प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि पीबीएल शिक्षण पद्धति शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थी रटने के बजाय वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझकर उनका व्यावहारिक समाधान खोजना सीखेंगे।

उन्होंने कहा कि इस पद्धति से

डायट में 250 शिक्षकों को दिया गया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का प्रशिक्षण

विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की योग्यता विकसित होगी। इसमें बच्चे समूह में कार्य करते हुए विषयों की गहराई से जानकारी जुटाते हैं और अपने ज्ञान को मॉडल, उत्पाद अथवा प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं।

प्रशिक्षक सुशील उपाध्याय ने बताया कि पीबीएल की अभिकल्पना सात चरणों में पूरी होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है।

प्रशिक्षक सतीश मौर्य ने बताया कि प्रशिक्षण के अंतर्गत आयोजित होने वाले पीबीएल मेले में विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान विषय पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

प्रशिक्षण में जूनियर हाईस्कूल स्तर के विज्ञान एवं गणित विषयों से जुड़े सात विकास खंडों के कुल 250 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, कक्षा संचालन, मूल्यांकन और प्रोजेक्ट प्रदर्शनी की तैयारी के लिए दक्ष बनाना है।

इस अवसर पर डायट प्रवक्ता अश्वनी पांडेय, अमित यादव, सुशील उपाध्याय, सतीश मौर्य, सीनिध सिंह, पूजा मालवीय, अनुपम श्रीवास्तव एवं सुजीत सोनकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।



आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलें खा रहे

खजुरन समेत बदलापुर के कई गांवों में गेहूं, सरसों और सब्जियों को नुकसान

बदलापुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तहसील के खजुरन समेत आसपास के कई गांवों में आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गेहूं, आलू, सरसों और सब्जियों की फसल बचाने के लिए किसानों को रात में खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि दिनभर मेहनत से फसल तैयार करने के बाद उन्हें रात में पशुओं को भगाना पड़ता है। ठंड और खराब मौसम में भी वे खेतों में जागते हैं। इसके बावजूद पशुओं के झुंड कई बार फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं।



खेती की लागत बढ़ने और फसल खराब होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह समस्या और मुश्किल बन गई है।गांवों की सड़कों और मुख्य मार्गों पर पशुओं के जमावड़े से हादसों की आशंका भी बढ़ रही है। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में रखने की मांग की है। उन्होंने गोशालाओं की नियमित निगरानी और पशुओं के लिए चारा-पानी व देखभाल की व्यवस्था करने को भी कहा है। किसानों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर फसलों को आवारा पशुओं से बचाने की मांग की है।

पद्मश्री डॉ. लालजी सिंह के सम्मान में लगा स्मृति द्वार, क्षेत्रवासियों में हर्ष



जौनपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2020 में सिकरारा से बरईपार मार्ग का नामकरण महान वैज्ञानिक एवं पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय डॉ. लालजी सिंह के नाम पर किया गया था। इसी क्रम में 17 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय विधायक लकी यादव द्वारा उक्त मार्ग पर पद्मश्री डॉ. लालजी सिंह के नाम से स्मृति द्वार स्थापित कराया गया। स्मृति द्वार स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों में वर्ष के साथ खुशी और उत्साह का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने इसे महान वैज्ञानिक डॉ. लालजी सिंह के प्रति सम्मान और उनकी स्मृतियों को संजोने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर राहुल महाविद्यालय, कलवारी, शेरवा, जौनपुर के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार श्रीवास्तव एवं आचार्य पं. राजीव मिश्र ने कहा कि पद्मश्री डॉ. लालजी सिंह के नाम पर स्थापित यह स्मृति द्वार क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। उनके जीवन, संघर्ष, वैज्ञानिक उपलब्धियों और योगदान से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने तथा देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्वों के नाम पर स्थापित ऐसे स्मृति चिह्न आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान और उपलब्धियों से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने साप्ताहिक परेड की ली सलामी, पुलिस लाइन में किया निरीक्षण



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। रिजर्व पुलिस लाइन जौनपुर में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनन्त चन्द्रशेखर ने ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों के टर्नआउट, वर्दी और अनुशासन का जायजा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को वर्दी स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम एवं ड्रिल कराई गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को अनुशासन बनाए रखने और अपनी कार्यक्षमता बेहतर रखने के निर्देश दिए। इसके उपरांत अर्दली रूम में संबंधित पुलिसकर्मियों के विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया।

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत मेडिकल कॉलेज में चला येलो लाइन कैंपेन



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर में येलो लाइन कैंपेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने युवाओं को तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशे की लत स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह, एफएसएसी जयप्रकाश गुप्ता, डीईओ कुलदीप श्रीवास्तव सहित मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया।

किसान सम्मान के लिए प्रगतिशील किसान 30 नवम्बर तक करें आवेदन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भूतपूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि 23 दिसंबर को हर वर्ष किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को राज्य व जनपद स्तर पर सम्मानित किया जाता है। जनपद के प्रगतिशील किसान इस योजना में शामिल होने के लिए 30 नवम्बर तक आवेदन कर पंजीकरण कराए। किसानों की फसलों के क्राप कटिंग परिणाम के आधार पर प्रतियोगिता कराई जाती है। खरीफ और रबी फसलों में सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसानों को जनपद स्तर पर प्रथम पुरस्कार सात हजार रुपए व द्वितीय पुरस्कार पांच हजार रुपए, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्रम देकर जनप्रतिनिधि व जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। जनपद में इस वर्ष 36 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि 23 दिसंबर को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले किसान सम्मान दिवस में प्रतियोगिता के लिए खरीफ फसलों के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उन्होंने जनपद के किसानों से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने उपज परिणाम निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर कृषि भवन में आवेदन कर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसानों की सूची जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन होने के पश्चात प्रदेश स्तर पर भी प्रेषित की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर स्थान बनाने वाले कृषकों को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रुपए एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कृषकों को 50 हजार रुपए देकर सम्मानित किया जाता है। प्रदेश स्तर पर कुल 58 कृषकों को सम्मानित किया जाता है।

सनराइज की पहल से अपनों के नाम समर्पित हुई छठ प्रभाती



गयाजी (उत्तरशक्ति)। छठ पर्व पर सनराइज ने अपनों के नाम छठ प्रभाती की अनूठी पहल की। इसके तहत श्रद्धालुओं को अपने बच्चों, जीवनसाथी और अन्य प्रियजनों के नाम से खास भक्ति गीत तैयार करने का अवसर मिला। सनराइज के व्हाट्सऐप बॉट के जरिए गयाजीवासी अपनी प्रभाती बनाकर उसे सुन और साझा कर सके। आईटीसी लिमिटेड के सनराइज स्पाइसेज के बिजनेस हेड सुरेश चाँद ने कहा कि ब्रांड का प्रयास छठ की सुंदर परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और परिवारों की प्रार्थनाओं को विशेष पहचान देने का था। इस पहल के माध्यम से पारंपरिक छठ गीतों में आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया। यह पहल डिजिटल होती दुनिया में इस प्रिय परंपरा से एक नया और आत्मीय जुड़ाव बनाती है।

सुर ताल संगम के बाल दिवस एवं दीपावली मिलन समारोह में संगीत, नृत्य और मनोरंजक खेलों ने बांधा समां

आचार्य सूरजपाल यादव

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था सुर ताल संगम की ओर से बाल दिवस एवं दीपावली मिलन समारोह ह्यबाल उमंगह्न रोशनी के संगह्न का भव्य आयोजन सुर ताल संगम म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ओमैक्स सिटी, शहीद पथ, लखनऊ में किया गया। समारोह में बच्चों ने संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थान के प्रशिक्षुओं एवं उनके अभिभावकों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना तथा बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि विकसित करना था। लोकप्रिय संगीत प्रशिक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त गायक अविजित श्रीवास्तव की परिकल्पना



पर आयोजित इस समारोह में संगीत, कला और मनोरंजन के जरिए बच्चों के बचपन की खुशियों को उत्सव का रूप दिया गया। साथ ही दीपावली मिलन के माध्यम से आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशियां बांटने का संदेश दिया गया। समारोह में संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मुंबई से आईं आद्या श्रीवास्तव ने अपनी सुमधुर गायकी से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वरिष्ठ कलाकार सीमा श्रीवास्तव और हिमांशु वर्मा के साथ अव्युक्त, रुद्रांश, आद्या सिंह, युविका पांडेय, आद्या बाजपेई, अद्विका पांडेय और त्रिनभ साहू सहित अन्य बाल कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। मनोरंजक खेलों में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर संस्था की डायरेक्टर डॉ. जया श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी प्रतिभा को पहचानना, प्रोत्साहित करना और उसे निखारने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराना संस्था की प्राथमिकता है। सुर ताल संगम संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के समापन पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने आयोजन की सफलता पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को गिफ्ट हैंपर भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया।

श्री जलाराम बप्पा का 227वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया



वसई। वसई गांव गुजराती लोहाना समाज परिवार की ओर से प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी श्री जलाराम बप्पा का 227वां जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वसई गांव के परनाका स्थित अन्नासाहेब वर्तक सभागृह में विशेष दर्शन एवं आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में वसई-विरार शहर महानगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष मनोज पाटिल, भाजपा महासचिव मनोज बारोट सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने श्री जलाराम बप्पा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने श्री जलाराम बप्पा के चरणों में नमन करते हुए समाज एवं क्षेत्र के सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहने की कामना की।

आईसीआईसीआई लाइफ सिग्नेचर पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना के साथ-साथ देता है अगली पीढ़ी को संपत्ति हस्तांतरित करने की सुविधा

ठाणे। आईसीआईसीआई लाइफ सिग्नेचर पेंशन लोगों को बाजार संबद्ध (मार्केट-लिंक्ड) रिटर्न के जरिए संपत्ति सृजन और कर-मुक्त विरासत (लिगेसी) तैयार करने की योजना बनाने का विकल्प प्रदान करता है। इसमें 90 साल की उम्र तक निवेश बनाए रखने (वेस्टिंग एज) के विकल्प है, जिससे ग्राहक 40 की उम्र में भी इस प्लान को शुरू कर सकते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखकर कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) का लाभ उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य उत्पाद अधिकारी, विकास गुप्ता ने इस उत्पाद के बारे में कहा, सेवानिवृत्ति और विरासत की योजनाएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं।

हालांकि, ऐसी वित्तीय योजनाएं जटिल हो सकती हैं और इनमें कर से जुड़े विभिन्न पहलू भी शामिल हो सकते हैं। आईसीआईसीआई लाइफ सिग्नेचर पेंशन को इस तरह तैयार किया गया है कि यह इन दोनों समस्याओं को हल करता है। यह उत्पाद ग्राहकों को कई तरह के फंड विकल्पों के साथ मार्केट-लिंक्ड कोष तैयार में मदद करता है। सेवानिवृत्ति के समय, कुल फंड का 60% तक हिस्सा कर-मुक्त निकाला जा सकता है, जिसे अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में दिया जा सकता है। बाकी बची हुई राशि का इस्तेमाल एन्युटी (वार्षिकी) उत्पाद खरीदने के लिए किया जा सकता है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन सुनिश्चित आय (गारंटीड इनकम) मिलती है। दीर्घकालिक संपत्ति सृजन और मार्केट-लिंक्ड रिटर्न को साथ जोड़कर, यह प्लान ग्राहकों और उनके प्रियजनों के लिए सेवानिवृत्ति और विरासत तैयार करने की योजना बनाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।

बेंगलुरु में महिला नेतृत्व को मजबूत करने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल हुईं स्नेहा दुबे पंडित

बेंगलुरु। बेंगलुरु के प्रसिद्ध विधान सौधा में आयोजित कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियन्स (CWP) इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वसई विधानसभा क्षेत्र की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाना रहा।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष जी.एस. पाटिल, CWP इंडिया रीजन की अध्यक्ष दग्गुबाती



पुरंदेश्वरी सहित देशभर से आईं महिला सांसदों एवं विधायकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में समावेशी शासन व्यवस्था, राजनीति में महिलाओं की प्रभावी भूमिका, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन तथा विधायी एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। विधायक स्नेहा दुबे पंडित की इस सम्मेलन में सहभागिता महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व को दर्शाती है। सम्मेलन ने देशभर की महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने और लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

महिलाओं की आवाज, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

पालघर जिले में स्वतंत्र जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना का रास्ता साफ

पालघर। पालघर जिले की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने पालघर में स्वतंत्र जिला एवं सत्र न्यायालय (मेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट) के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) न्यायालय स्थापित करने तथा सरकारी अभियोजक कार्यालय सहित आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस निर्णय को पालघर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विधायक स्नेहा दुबे पंडित द्वारा लगातार की जा रही मांग और प्रयासों को इससे महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

गौरतलब है कि 1 अगस्त 2014 को ठाणे जिले का विभाजन



कर पालघर को स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था। हालांकि प्रशासनिक रूप से जिला अलग हो गया था, लेकिन न्यायिक प्रशासन के लिए पालघर जिले को ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। इसके कारण जिले के न्यायिक मामलों का नियंत्रण ठाणे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीन था।

वर्तमान में वसई, पालघर और जव्हार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तथा दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ एवं वरिष्ठ स्तर के न्यायालय कार्यरत हैं। इसके बावजूद पालघर में स्वतंत्र जिला न्यायपालिका के सर्वोच्च पद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने पालघर जिले में स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन स्थापित करने की आवश्यकता को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। उनकी इस मांग पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय जिले के न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस निर्णय के बाद नागरिकों को कई महत्वपूर्ण दीवानी एवं आपराधिक अपीलों, प्रशासनिक न्यायिक प्रक्रियाओं तथा अन्य मामलों के लिए ठाणे तक जाने की आवश्यकता कम होगी। अब ऐसे मामलों का निपटारा पालघर में ही हो सकेगा। विशेष रूप से जव्हार, मोखाडा, दहानू और तलासरी जैसे दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिकों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। साथ ही जिले के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों के बेहतर नियंत्रण, न्यायिक कार्यों में समन्वय और मामलों के त्वरित निपटारे में भी मदद मिलेगी।

विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि पालघर जिले की स्थापना के बाद यहां स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई थी और अब सक्षम एवं प्रभावी न्यायिक व्यवस्था की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारा प्रयास है कि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए अनावश्यक यात्रा, समय और आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। पालघर जिले के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ आम नागरिकों को सुलभ, सरल और प्रभावी न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

जुहू चौपाटी पर पूर्णिमा वर्ल्ड छठ पूजा समिति का भव्य छठ महोत्सव, मैथिल समाज ने धूमधाम से मनाया लोक आस्था का पर्व

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई के जुहू चौपाटी पर पूर्णिमा वर्ल्ड छठ पूजा समिति (मैथिल समाज) की ओर से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भव्य सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समाज के गणमान्य लोगों ने सहभागिता निभाई। छठ महापर्व के अवसर पर व्रतधारियों ने परंपरागत विधि-विधान से भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की। संध्याकाल में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया, जबकि दूसरे दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत की परंपरा पूरी की गई। पूरे आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में श्री राधे म्यूजिकल ग्रुप के गायक दिनेश चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा भजन-कीर्तन, पारंपरिक गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। छठी मैया के गीतों और भक्तिमय संगीत से पूरा वातावरण भक्तिरस में डूब गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों की रही विशेष उपस्थिति इस धार्मिक आयोजन में अमित साटम, पवन त्रिपाठी, दीपक कोटकर, सुधा सिंह, अनीस मकवानी, विट्ठल बंदरी और विश्वजीत चंद सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने छठ पूजा में शामिल होकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। समिति के पदाधिकारियों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्णिमा वर्ल्ड छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। समिति के प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम में हरिओम ठाकुर, अनिता मंडल, सुभाष महतो, कृष्णा मंडल, भव्य विनोद चौधरी, श्याम यादव, अनिल भाई, डॉ. ममता महतो, राजकिशोर सिंह, गणेश यादव, मनोज मंडल, दिनेश पासवान, घूरन यादव, प्रदीप ठाकुर, प्रेम ठाकुर, बलराम ठाकुर, संतोष राय, राजेश राय, राम भगत यादव और भुवन महतो सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूर्णिमा वर्ल्ड छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव ने धार्मिक आस्था के साथ मैथिल समाज की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।

बाला ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना को नई ताकत, अनंतनाग में दो दर्जन युवा पार्टी से जुड़े

श्रीनगर। शिवसेना संस्थापक हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने अनंतनाग में नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकताओं ने बालासाहेब ठाकरे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान करीब दो दर्जन स्थानीय युवाओं ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं के अनुसार ये युवा पार्टी की जनहितैषी नीतियों, विचारधारा और जम्मू-कश्मीर के स्थानीय मुद्दों तथा लोगों के अधिकारों को लेकर पार्टी द्वारा उठाई जा रही आवाज से प्रभावित थे।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने हमेशा आम जनता और स्थानीय लोगों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा। 'लोकल फर्स्ट' का सिद्धांत महज नारा नहीं, बल्कि पार्टी की राजनीतिक प्रतिबद्धता और बालासाहेब के विचारों की असली



विरासत है। साहनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जमीन, प्राकृतिक संसाधनों, बिजली, सरकारी नौकरियों और व्यापारिक अवसरों पर पहला अधिकार स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों को सस्ती और मुफ्त बिजली का लाभ मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के साथ स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना स्थानीय लोगों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी। पार्टी इन मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। साहनी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम में कश्मीर प्रभारी संजय भट्ट, जिला अध्यक्ष हिलाब मोहम्मद, सह-समन्वयक उमर याकूब, ओबीसी जिला अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, उपाध्यक्ष शाहनवाज अहमद और तारिक अहमद सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।



